भारत में जापानी विद्युत परियोजनायें

4456. श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में टोकियों में संपन्न हुये भारत-जापान व्यापार सहयोग सम्मेलन में भारत में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत जापानी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में भारत और जापान के बीच किन्ही निबंधनों तथा शर्तों पर सहमति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो वे निबंधन तथा शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मामलों में जापान भारत पर दबाव डाल रहा है । यदि हां, तो जापान द्वारा भारत पर दबाव डालने का उद्देश्य तथा मंशा क्या हैं ; और

(ङ) निजीकरण के संबंध में निर्धारित नीतियों को ध्यान में रखते हुये सरकार इस संबंध में क्या और कब निर्णय लेने का विचार रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल): (क) से (ङ) दिनांक 6 और 7 अप्रैल, 1995 को आयोजित जापान-भारत व्यवसाय सहयोग समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई थी कि विद्युत उत्पादन में जापान की भागीदारी की व्यापक क्षमता है । भारत में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में, जब जापानी पक्ष ने केन्द्रीय सरकार की गारन्टियों की आवश्यकता पर जोर दिया, तब भारतीय पक्ष ने कहा कि भावी परियोजनाओं के लिये ये संभव नही होंगी । तथापि, भारतीय पक्ष ने यह कहा था कि भारत सरकार प्रति-गारंटी के वैकल्पिक समाधानों के बारे में कार्रवाई कर रही है ।

Private Sector involvement in power generation

4457. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it s a fact that a long time has passed since Government decided to handover power generation to private sector;

(b) the number of power projects handed over to private sector till date;

(c) the present position of these projects; and

(d) the future plans of Government in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The private power policy, enabling private sector participation in electricity generation, supply and distribution, was introduced by the Government in October, 1991.

(b) No existing power projects has been handed over to the private sector. However as per information made available by various State Governments|State Electricity Boards Power Grid|Energy Management Centre, New Delhi, 190 expressions of interest have been received for setting up power projects in the private sector.

(c) Out of these 190 projects, Memorandum of Understanding have been signed in the case of 123 projects; 14 projects have been cleared from the foreign investment angle; 11 projents have been techno-economically cleared by the Central Electricity Authority. One project,